चार हजार करोड़ की परियोजना से बढ़ेगी कृषि पैदावार

यूपी एग्रीज के तहत विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच समझौता, 28 जिलों में चलाई जाएगी परियोजना

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट (यूपी एग्रीज परियोजना) के तहत समझौता ज्ञापन पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना कम पैदावार वाले 28 जिलों में चलाई जाएंगी। इनमें पूर्वी यूपी के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं। इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह लगभग चार हजार करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसमें तीन हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। इसे 35 वर्षों में चुकाया जाएगा और लगभग सात वर्ष का मोरेटोरियम पीरियड (किस्त चुकाने से छूट का समय) है। उन्होंने कहा कि मत्स्य सेक्टर को भी योजना में शामिल किया गया है। इसमें असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सालाना 40 मिलियन टन फल एवं सब्जियां पैदा करता है। जेवर एयरपोर्ट के निकट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग का क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जहां फलों व सब्जियों के ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

बाद में कारगो प्लेन से बाहर भेजा जाएगा। देश में यूपी पहली बार ऐसी व्यवस्था कर रहा है। अभी तक उत्पादों को जलमार्गों अथवा पैसेंजर प्लेन में सामान (लगेज) के साथ भेजा जाता था। वाराणसी स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें पार्टनर के रूप में कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यूपी एग्रीज परियोजना का असर न केवल प्रदेश की जीडीपी पर पड़ेगा, बल्कि इस सेक्टर से जुड़े प्रदेश की 60 फीसदी आबादी की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।

करार पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने हस्ताक्षर किए। -सूचना विभाग